

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा –डिजिटल इंडिया एक जन आंदोलन बन गया है।
- जीएसटी लागू होने के आठ साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने कहा यह आर्थिक विकास के लिए शक्तिशाली इंजन के रूप में काम कर रहा है।
- द्वीप वनों के संरक्षण के लिए एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत रंगत में मनाया गया वन महोत्सव।
- भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण में हुआ दो दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन।

&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;

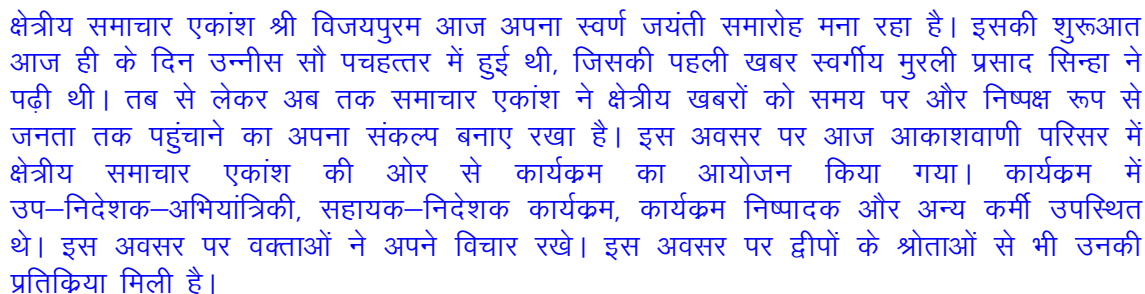
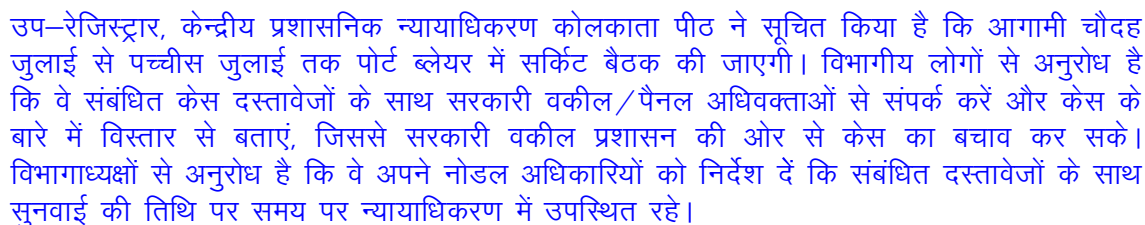
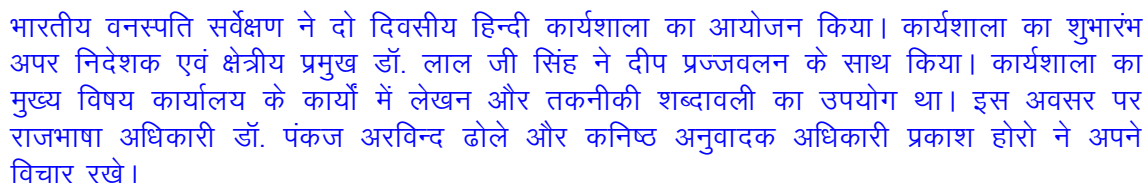
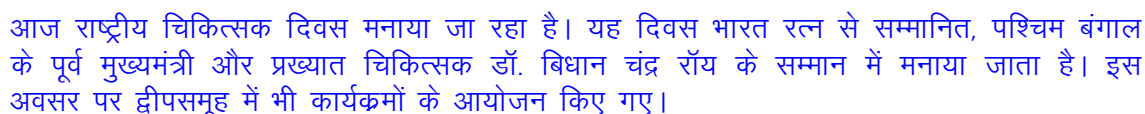
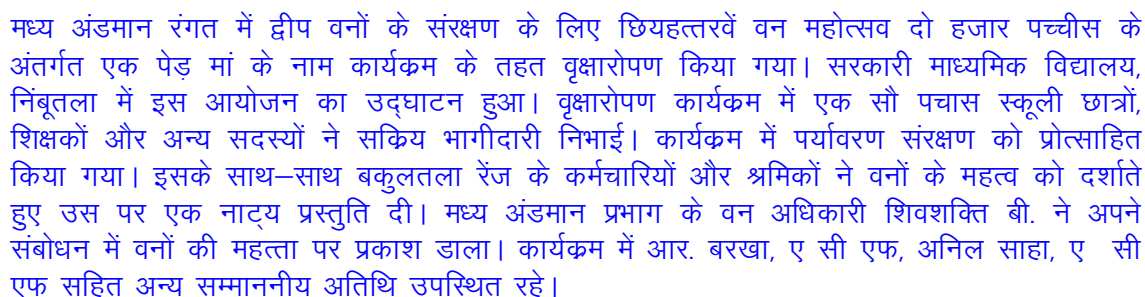
डिजिटल इंडिया के दस वर्ष पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि यह एक जन आंदोलन बन गया है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में विश्वसनीय भूमिका निभा रहा है। एक ब्लॉग में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत डिजिटल शासन से वैश्विक डिजिटल नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। डिजिटल इंडिया ने देश के आम नागरिकों को तकनीक से जोड़ा है, जिससे लोगों का जीवन आसान हुआ है। इस के माध्यम से देश के दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट की सुविधा पहुंचाई गई है और सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है। अब लोग महज एक क्लिक से स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग और अन्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। डिजिटल इंडिया अभियान के कारण देश के लगभग हर गांव में मोबाइल कनेक्टिविटी का विस्तार हुआ है। डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर के माध्यम से चवालीस लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं। डिजिटल सेवाओं ने शासन को तेज और अधिक पारदर्शी बना दिया है। यूपीआई उपयोगकर्ताओं को स्मार्टफोन का उपयोग करके बैंक को तुरंत धन हस्तांतरित करने की अनुमति देता है और आज लगभग छियालीस करोड़ लोग और छः करोड़ से अधिक व्यापारी यूपीआई का उपयोग कर रहे हैं।

&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;

जीएसटी लागू होने के आठ साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जीएसटी यह एक ऐतिहासिक सुधार के रूप में सामने आया है, जिसने भारत के आर्थिक परिदृश्य को नया आकार दिया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने संदेश में कहा कि इसने विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए व्यापार करने में आसानी में बहुत सुधार किया है। जीएसटी ने आर्थिक विकास के लिए एक शक्तिशाली इंजन के रूप में भी काम किया है और साथ ही भारत के बाजार को एकीकृत करने की इस यात्रा में राज्यों को समान भागीदार बनाकर सच्चे सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया है।

&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण पर विशेष ध्यान देते हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने और सामाजिक सुरक्षा के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में मीडिया को मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अंतर्गत पहली बार नौकरी पर आए कर्मचारियों को एक महीने का वेतन पन्द्रह हजार रुपये तक मिलेगा। उन्होंने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र में दो वर्ष के लिए विस्तारित लाभ के साथ अतिरिक्त रोजगार पैदा करने के लिए नियोक्ताओं को दो वर्ष तक प्रोत्साहन लाभ दिया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक लाख करोड़ रुपये की निधि के साथ अनुसंधान विकास और नवाचार योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य देश के अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देकर दीर्घकालिक वित्तपोषण करना है। उन्होंने कहा कि देश में खेल परिदृश्य को बदलने और खेल गतिविधियों के साथ नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय खेल नीति-2025 को भी मंजूरी दी गई है।



आई पी एंड टी निदेशालय चौबीस, पच्चीस, छब्बीस जुलाई को आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट बंगलुरु में भाग लेने के लिए ऑपरेटरों और ट्रैवल एजेंटों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति तीस हजार रुपये की भागीदारी शुल्क के साथ सात जुलाई शाम चार बजे तक वरिष्ठ लेखा अधिकारी आई पी एंड टी निदेशालय के पक्ष में डी डी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

<><><><><><><>